

केरल लोकायुक्त की शक्तियों में कमी

प्रलिस के लयः

लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013 ।

मेन्स के लयः

लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013, लोकपाल के कामकाज से जुड़े मुद्दे और आगे की राह, भ्रष्टाचार वरिधी उपाय ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल वधानसभा ने [केरल लोकायुक्त \(संशोधन\) वधियक, 2022](#) पारति कयि ।

संशोधनः

- यह संशोधन वधियक **लोकायुक्त के आदेश के बाध्यकारी पहलू को कमजोर कर दयि है**, जससे सकषम प्राधकिरी अब लोकपाल की रपिर्ट को या तो अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है ।
 - संशोधन दवारा राज्य सरकार को **भ्रष्टाचार वरिधी नकिय के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्तिमलि जाएगी** ।
 - संशोधन लोकायुक्त को सरिफ सफिरशिं करने या सरकार को रपिर्ट भेजने के लयि एक नकिय बना देगा ।
- इसने **वधानसभा** को मुख्यमंत्री के खलिफ अभयिग रपिर्ट की समीक्षा करने के लयि **सकषम प्राधकिरी भी बनाया है** ।
 - अगर लोकायुक्त की रपिर्ट में कैबनित मंत्री को दोषी ठहराया जाता है, तो वधियक मुख्यमंत्री में समीक्षा करने का अधकिर देता है ।
 - **वधियकों के मामले में सकषम प्राधकिरी सदन के अध्यक्ष होंगे** ।
- **वधियक राजनीतिक नेताओं को अधनियम के दायरे से छूट देता है** ।
- वधियक **उच्च न्यायालय के सेवानवृत्त न्यायाधीशों को लोकायुक्त नयिक्त करने की अनुमति देता है**
- अधनियम की धारा 14, जसिं अब संशोधति कयि गया है, के अनुसार, यद लोकायुक्त लोक सेवक के खलिफ शकियत पर संतुष्ट हो जाता है कउसे अपने पद पर बने रहना आवश्यक नहीं है, तो वह सकषम प्राधकिरी को अपनी रपिर्ट में इस आशय की घोषणा करेगा जो इसे स्वीकार कर उस पर कार्रवाई करेगा ।
 - दूसरे शब्दों में यद लोक सेवक मुख्यमंत्री या मंत्री है, तो वह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देगा **ऐसा प्रावधान राज्य के कसिी भी कानून या केंद्र के लोकपाल अधनियम में मौजूद नहीं है** ।

लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणाः

- **लोकपाल तथा लोकायुक्त अधनियम, 2013** ने संघ (केंद्र) के लयि लोकपाल और राज्यों के लयि लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की ।
- इन संस्थाओं को संवैधानकि दर्जा प्राप्त नहीं है, अतः ये संस्थाएँ वैधानकि नकिय हैं ।
- ओम्बड्समैन या लोकपाल का कार्य कुछ नशिचति श्रेणी के सरकारी अधकिरयिों के वरिद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना है ।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013 लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है । लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूरव मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूरव न्यायाधीश या असंदगिध सत्यनषिठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात वयक्ति होना चाहयि ।
 - आठ अधकितम सदस्यों में से आधे न्यायकि सदस्य तथा कम-से-कम 50 प्रतशित सदस्य अनु. जात/अनु. जनजात/अन्य पछिड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहयि ।
- लोकपाल को **मार्च 2019 में नयिक्त** कयि गया था और इसने **मार्च 2020 से कार्य करना शुरू** कर दयि था, जब इसके नयिम बनाए गए थे ।
- वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के पूरव मुख्य न्यायाधीश **प्रदीप कुमार मोहंती** लोकपाल के प्रमुख है ।
- लोकपाल के पास कसिी ऐसे वयक्ति के वरिद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधकिर क्षेत्र है **जोप्रधानमंत्री, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य, साथ ही समूह A, B, C और D के तहत केंद्र सरकार के अधकिरी हैं** ।

- इसके अलावा किसी भी बोर्ड, नगिम, समाज, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और नदिशक शामिल हैं जो या तो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं।
- यह किसी भी समाज या ट्रस्ट या निकाय को भी शामिल करता है जो 10 लाख रुपए से अधिक का वदिशी योगदान प्राप्त करता है।

लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित चिंताएँ:

- लोकायुक्त कानून को सार्वजनिक पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, वधायकों आदि के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये अधिनियमिति किया गया था, जो भ्रष्टाचार नविारण अधिनियम के अंतरगत आते हैं। इस अधिनियम के परभाषा खंड में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है।
 - मूल रूप से भ्रष्टाचार नविारण अधिनियम सरकार और संबद्ध एजेंसियों, वैधानिक निकायों, नरिवाचित निकायों आदि में भ्रष्टाचार से संबंधित है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
 - इसलिये इन्हें लोकायुक्त अधिनियम के दायरे लाना मुश्किल कार्य है।
- इस कानून में एक और समस्यात्मक प्रावधान है, जो लोकायुक्त (धारा 12) की रिपोर्ट से संबंधित है।
 - इसमें कहा गया है कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होने पर, कार्रवाई की सफिराशि के साथ नषिकर्षों को सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, जसि लोकायुक्त की सफिराशि के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
 - इसमें आगे कहा गया है कि यदि लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो वह मामले को समाप्त कर देंगे। सवाल यह है कि लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार के मामले को कैसे बंद कर सकता है जो एक आपराधिक मामला है और जसिमें 11 से सात वर्ष की कैद का प्रावधान है।
 - लोकपाल ने जाँच के बाद न्यायालय में केस दायर करता है। केंद्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जसिके तहत लोकपाल मामले को न्यायालय में पहुँचने से पूर्व ही समाप्त कर दे।

आगे की राह:

- भ्रष्टाचार के वरिद्ध लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिये राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों के व्यापक सुधार अनविार्य है।
- केरल लोकायुक्त अधिनियम की वधिानसभा की एक समिति द्वारा पुनः जाँच की जानी चाहिये और इसे लोकपाल अधिनियम के अनुरूप होना चाहिये।

स्रोत: द हद्रि

